

संख्या-15011/36/2022-जे यू एस (एयू)/6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

-----

**विषय: न्याय विभाग से संबंधित मार्च 2023 का मासिक सार ।**

मार्च, 2023 से संबंधित न्याय विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं ।

1. **केन्या की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत** : न्याय विभाग ने केन्या की मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति मार्था कूमे और उनके प्रतिनिधिमंडल की उनके दिल्ली आगमन पर मेजबानी की । केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने 10 मार्च, 2023 को होटल अशोका, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री और न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की । विधि और न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों ने केन्याई प्रतिनिधिमंडल के समक्ष अपने प्रमुख कार्यों, भूमिकाओं और मुख्य उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद दोनों देशों की न्यायिक प्रक्रियाओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ ।

2. **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-1।**

(क) **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड**: दिनांक 01-03-2023 की स्थिति के अनुसार वादीगण राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर 22.38 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 20.83 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) **वर्चुअल कोर्ट**: 21 वर्चुअल कोर्ट द्वारा 2.53 करोड़ से अधिक मामलों में सुनवाई की गई है और दिनांक 31-01-2023 तक 33 लाख से अधिक मामलों में 359 करोड़ रुपए से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है।

(ग) **ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप**: दिनांक 28-02-2023 तक ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या कुल 1.70 करोड़ हो गई है।

3. **टेली लॉ प्रोग्राम**:

(क) 31 मार्च, 2023 तक , 35,57,395 लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई थी जिसमें केवल मार्च, 2023 माह के दौरान 2,02,850 लाभार्थियों को दी गई कानूनी सलाह भी शामिल है।

(ख) माह के दौरान वीएलई/पीएलवी, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 105 जिलों में आयोजित 126 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों/कैंपों में 3908 व्यक्तियों ने भाग लिया।

4. **न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विस) :**

(क) माह के दौरान, 260 नए प्रो-बोनो वकील न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हुए। कुल 6214 वकील (पुरुष 5256, महिला 956, ट्रांसजेंडर-02) न्याय बंधु पोर्टल के तहत पंजीकृत हुए हैं।

(ख) माह के दौरान 9 नए वकीलों का उच्च न्यायालयों में नामांकन किया गया जिससे उच्च न्यायालयों में अब तक प्रो बोनो वकीलों की कुल संख्या 1256 हो गई है।

5. **पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम :**

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों के संरक्षण पर पन्द्रहवीं वेबीनार कानूनी जागरूकता वेबीनार सेवाओं के अंग के रूप में न्याय विभाग द्वारा दिनांक 06-03-2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 29,851 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। परस्पर वार्ता सत्र में विधि कॉलेजों के प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण पर सोलहवीं वेबीनार का आयोजन भी न्याय विभाग द्वारा दिनांक 28-03-2023 को किया गया और इसमें 21,143 प्रतिभागी उपस्थित थे। उपभोक्ता अधिकार पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सत्र में भाग लिया।

(ख) सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओईडीसीओएन), जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान के करौली जिले में पंचायत स्तर की 20 संवेदीकरण बैठकें, 20 धानी बैठकें, और 7 व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

xxxxxxx